number of other agricultural commodities.

Therefore, in the interests of agricultural production, in the interests of the Second Five Year Plan and the consumer, in the interests of the small peasants who produce these things, I would say that Government must immediately set up a committee to go into the whole question of fixing some parity price, integrated price so that the country would not be in this plight.

After the Second Five Year Plan, we might talk of the *per capita* income having gone higher. But, if this sort of price policy is to continue we will find the peasant, the consumer, the producer, 80 per cent. of the people would not see any growth in national income. It is in this aspect that Government should accept this Resolution and set up the Committee immediately.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

Secretary: Sir, I have to report the following message received from the Secretary of Rajya Sabha:—

> 'In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 162 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the *Appropriation (No. 4)* Bill, 1957, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 24th August, 1957, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill.'

RESOLUTION *RE*: APPOINTMENT OF A COMMITTEE TO REPORT ON A CLEAR-CUT POLICY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE SECOND FIVE YEAR PLAN—*contd.*

Mr. Deputy-Speaker: I have still some 7 or 8 minutes more. If any hon. Member wants to speak I can allow.

Shri Bimal Ghose: If you can give me 10 to 12 minutes, I can speak.

Mr. Deputy-Speaker: No; I have to call the Minister at 4-36.

श्री बनगर (मैनपुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने फूड प्राइसिज का प्रश्न है । खाद्य पदार्थों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं । इस समस्या को हल करने के लिये गवर्नमेंट बहुत दिनों से तरह तरह की तजवीजें ला रही है, लेकिन यह समस्या सुलझ नहीं रही है और जहां तक मौजूदा सरकार का संबंध है, मैं समझता हूं कि वह इस को हल करने में कदापि सफल नहीं हो सकेगी । इसकी मुख्य वजह यह है कि हमारे देश में बहुमत किसानों और मजदूरों का है, लेकिन अगर हम सरकार की तीनों अंगों—जुडिशरी, एग्जीक्युटिव और लैजिस्लेचर—का ख्याल करें, तो हम देखते हैं कि उनमें ज्यादा तादाद उन लोगों की नहीं है, जो कि देश के सही नुमाइंदे हो सकते हैं । यही खास वजह है कि हम अपनी जटिल समस्याओं को, जो कि हमारे देश के लिये या किसी भी देश के लिये मौलिक समस्यायें हो सकती हैं, हल करने में सफल नहीं होते हैं । जब तक इस सरकार में बहुमत किसानों का न होगा, मजदूरों का न होगा, उन लोगों का न होगा, जिनकी ये समस्यायें हैं, तब तक ये समस्यायें हल नहीं हो सकती हैं । आज इस देश में कांग्रेस पार्टी का राज्य है, जिसके सामने महात्मा गांधी ने यह आदर्श रखा था कि इस देश का राष्ट्रपति जब तक एक किसान नहीं होगा, तब तक इस देश का बेड़ा पार न हो सकेगा, लेकिन राष्ट्रपति तो क्या, सारे देश के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी संस्था में किसानों और मजदूरों का, जिनका कि इस देश में बहुमत है, सही प्रतिनिधित्व नहीं है । राज्य जैसी संस्था हो, या कोई भी संस्था हो, हर एक संस्था 'बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय' के लिये संगठित होती है, लेकिन इसका ठीक विपरीत अग